लोक सभा अध्यक्ष ने कहा भारत का विकास उत्तर पूर्व के विकास के बिना संभव नहीं।

आज त्रिपुरा के अगरतला में पन्द्रहवें उत्तर-पूर्व क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए लोक सभा की अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि भारत का विकास उत्तर पूर्व के विकास के बिना नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर पूर्व में अनुकूल महिला पुरुष अनुपात, समृद्ध प्राकृतिक संसाधन और ग्रामीण शिक्षित युवा जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। उनका मत था कि इस युवा कार्यबल का संपत्ति के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

इस अवसर पर श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि संतुलन की प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में राज्य के तीन महत्वपूर्ण अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाएं परिभाषित की गई हैं । सक्रिय लोकतंत्र में सतत विकास, स्थायी शांति और समावेशी विकास तभी संभव हो सकता है जब हमारे लोकतंत्र के सभी अंग देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सहयोगपूर्ण और सहभागिता पूर्ण ढंग से कार्य करें न कि प्रतिस्पर्धात्मक केंद्रों के रूप में । भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आधार के रूप में लचीली संस्थाओं की परिकल्पना की थी। श्रीमती महाजन ने कहा कि विधायी सप्रभुता और न्यायिक समीक्षा दो विशिष्ट सिद्धांत हैं जिनका हमारे संवैधानिक ढांचे में समान महत्व है और यह हमारी लोकतात्रिक प्रणाली का अनूठा पहलू है । उन्होंने यह भी कहा कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के साथ मीडिया को अपने - अपने संस्थागत ढांचे के भीतर रह कर कार्य करना चाहिए।

सम्मेलन की कार्यसूची के बारे में बोलते हुए श्रीमती महाजन ने कहा कि भूमि कटाव और इसके घातक प्रभावों को देशभर में देखा जा सकता है । भारी वर्षा और तीव्र गति से बहने वाली नदियों के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत अधिक भूमि कटाव होता है । मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आने और लंबे समय तक सूखा पड़ने के कारण भूमि कटाव होता है । इसलिए, अनेक विद्यमान तौर-तरीकों के कारण वन क्षेत्र के लगातार कम होने की समस्या के निदान के लिए अधिक स्थायी विकल्प विकसित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ।

लोक सभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण जल अभाव की स्थिति का गंभीर होना और भूमि की उर्वरता में लगातार गिरावट आना ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनसे खाद्य उत्पादन की भावी संभावनाओं और पर्यावरणीय स्थिरता को खतरा है । इसलिए सिंचाई क्षमता में सुधार लाने के लिए वर्षा जल संचयन, भूमि कटाव नियंत्रण, उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग जैसे विभिन्न भूमि और जल संरक्षण और प्रबंधन पद्धतियां विकसित करने और उन्हें कार्यान्वित करने के कार्य को प्राथमिकता दिए जाने की अत्यावश्यकता है ताकि उत्तर-पूर्व क्षेत्र की जलवायु संबंधी परिस्थरितियों में सुधार किया जा सके । उन्होंने विधायकों से इस मुद्दे से निपटने के लिए व्यवहार्य विकल्प विकसित करने के बारे में जागरूकता विकसित करने में मदद करने का आग्रह किया ।